SHRI K. V. THANGKA BALU: State level Commissions are appointed and the State level Commissions will take care of this problem. If there is any specific problem, the Government is willing to consider it...(*Interruptions*)... Sir, I understand the problem.

MR. CHAIRMAN: I understand that normally it is not admitted. In a State, the castes which they have categorized as backward would only be admitted as backward. Therefore, there will be a clash. How you will resolve it is the question.

SHRI K. V. THANGKA BALU: That is why the Commissions are appointed. The primary duty of the Commission is to identify the castes. They will identify and they will look into it.

MR. CHAIRMAN: You please look into it a little more in depth.

SHRI K. V. THANGKA BALU: I will look into it, Sir.

श्री एस०एस० सुरजेवाला : सभापति जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा का नाम भी उस लिस्ट में है जिन स्टेट्स ने ग्रदर बैकवर्ड क्लासेस को ग्रायडेंटीफाई किया है, तो क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि वह कौन सी जातियां हैं जिन को कि हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रायडेंटीफाई किया है, उनके नाम बतायेंगे ?

SHRI K. V. THANGKA BALU: Sir, Haryana has notified the list. I will send a copy of the list to the hon. Member, Sir.

...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: One more supplementary. Mrs. Renuka Chowdhury, are you interested?

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Yes, Sir. I want to know if there is a time-bound programme to expedite identification of the OBCs and what is the uniform rule that you bring for application to all. There are some communities in Andhra which are considered forward castes, and the same communities in Karnataka are considered OBCs. If this is the scheme that you are going to have, then how do you propose to have a uniform rule applied to all and how do you propose to bring about national integration on these lines? There will be uneven migration of a particular community from one State to another for getting those benefits, and there will be misuse.

SHRI K. V. THANGKA BALU: There cannot be any misuse, Sir. The very purpose of the State-level Commission is to identify and to include or to exclude the communities. The very purpose is that. So, there would not be any problem. If anybody is aggrieved, the problem will be sorted out by the Commission.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: All the States have not identified the same communities as OBCs.

MR. CHAIRMAN: He is saying that he will ask the Commission to look into it.

Now the Short-Notice Question.

...(*Interruptions*)...

Please. Will you kindly sit down. The business is going on.

SHORT NOTICE QUESTION

Transfer of 1,300 Acres of land to Punjab Agricultural University

*1. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the attention of the Government has been drawn to a News item published in Tribune dated 10th July, 1993 under the caption "1,300 acres for PAU";

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether hte interst of the workers will be safeguarded in the process of transfer of land to PAU; and

(d) the details of the steps being taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (d) The Central State Farm (CSF) Ladhowal was taken on lease from the Government of Punjab by the SFCI, for a period of 20 years with effect from 1-6-1971.

The Government of Punjab have been requesting the return of the Central State Farm at Ladhowal to strengthen the seed production programme of the Punjab Agricultural University since 1988. It has been decided to agree to the request of the Government of Punjab in consultation with the State Farm Corporation of India.

The overall welfare of the workers of the farm will be kept in view when the modalities of transfer are finalised.

श्री कृष्ण लाल शर्मा: सभापति महोदय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह उत्तर कुछ शंकायें भी पैदा करता है और वह पूरा उत्तर भी नहीं है। यह जो जमीन है, यह आज से 20 साल पहले पंजाब से, यह जमीन भी पूरी 2700 एकड़, 20 साल पहले उससे ली गई थी और यह स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इंडिया ने ली थी। इसका मैन परपज किसानों के लिए अच्छे बीज तैयार करके उनको बांटने का था। अब आज 20 साल के बाद यह निर्णय किया जा रहा है कि यह जमीन वापस पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दी जाएगी। एक तो इसमें यह समझ में नहीं आ रहा कि यह जमीन जिस परपज के लिए दी गई थी उसमें अगर अब काम पूरा नहीं हो रहा तो यह जमीन जहां से ली गई थी, पंजाब लेंड डवलपमेंट सीड कारपोरेशन पंजाब, उनको वापस क्यों नहीं दी जा रही? दूसरा, इसका बाइफरकेशन क्यों हो रहा है? और, तीसरा, एम्प्लाइज, यह जो सारे इसमें से दिए जा रहे हैं, न उसको कोई आश्वासन दिया जा रहा है, न जो किसानों को हम बीज दे रहे थे उसका कोई आश्वासन दिया जा रहा है और न जमीन के बारे में कहा जा रहा है कि जमीन को क्यों बांटा जा रहा है। सारी चीज को अनिश्चित किया जा रहा है और नई शंकायें पैदा हो रहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह 2700 एकड़ जमीन जो 20 साल पहले ली गई थी, इसको बाइफरकेट क्यों किया जा रहा है? फिर, दूसरा, इसको वापस जहां से लिया था उसी को क्यों नहीं दिया जा रहा? तीसरा, यह कि इसका जो परपज था इसको छोड़कर अब इसको क्या रिसर्च के लिए इस्तेमाल करेंगे? और, आखिरी बात, क्या जो एम्पलाइज इसमें थे, उन सबकी सर्विस कंडीशन को एनश्योर करते हुए, उसी कंडीशन में उनकी कण्ट्रब्यूटि कायम रखते हुए, उनको सब प्रकार के, जितने भी इस समय अनुदान मिल रहे है या सुविधायें मिल रही हैं उसकी गारण्टी देते हुए, किसानों को बीज देने की गारण्टी...

MR. CHAIRMAN: Kindly conclude now.

SHRI KRISHAN LAL SHARMA: I am concluding. और एम्पलाईज को उनकी सर्विस को एनश्योर करने की गारण्टी, किसानों को बीज देने की गारण्टी और इस लैण्ड को एक साथ रखने की गारण्टी, यह तीनों बातें में चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि यह गारण्टी क्या दी गई है इसमें? दी गई हैं, तो उसकी डिटेल क्या हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): सभापति जी, प्रश्न का उत्तर पूरा है, समझने की चेष्टा माननीय सदस्य करें तो समझेंगे कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बहुत बड़ा पार्ट पहले किया है देश के अनाज की उत्पत्ति में और आज उनको आवश्यकता इस बात की है कि उनको और जमीन भी चाहिए और इसीलिए उनके साथ कुछ बात की जा रही है और जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने आज तक किया

है, वह बेमिसाल है। वह बीज भी पैदा करती है और तकरीबन-तकरीबन पंजाब को आत्मनिर्भर बीज के लिए कर रखा है। यह भी उसी काम के लिए इस्तेमाल की जाएगी और उसे और अच्छा किया जाएगा। उनको जरूरत है, जो उनके पास है वह जमीन कम पड़ती है और यह किसान के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। अगर यह बात नहीं होती तो कभी किया ही नहीं जाता, प्रश्न ही नहीं पैदा होता कि किसान का नुकसान हो या बीज की उत्पत्ति न हो। यही नहीं, आइंदा ऐसा सिलसिला किया जा रहा है कि बीज उत्पत्ति के लिए नेशनल सीड्स कारपोरेशन और स्टेट फार्म्स कारपोरेशन, दोनों को मिलाकर के कुछ इस प्रकार का सम्मिश्रण उनका वहां किया जाएगा कि कोआपरेशन उनकी हो और ऐसे-ऐसे बीज पैदा करने के लिए बाहर के जो हमारे टैक्नीशियन हैं, जिनको मैं बुला रहा हूं, उनको बुलाकर के ऐसे बीज उत्पन्न करके दें जिससे किसानों के लिए और ज्यादा आमदनी का जरिया बन सके और इसलिए किया गया है। यह जो 94 के करीब हमारे पास उसमें काम करने वाले हैं, उनको तो काम मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दिया गया है कि जब उनकी मोडेलिटीज तय होंगी तो उनको बढ़ाना ही है, उन्हें घटाना नहीं है। जब काम बढ़ेगा, पंजाब में तो बाहर से लोग आकर काम करते हैं, वहां काम करने वालों की कमी है और इसीलिए बाहर से लोग आकर के काम करते हैं, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वहां कमी होने की गुंजाइश नहीं हो सकती, काम ज्यादा मिलने की गुंजाइश हो सकती है।

श्री कृष्ण लाल शर्मा : मंत्री महोदय, यह पहले जब लैंड ली गई तो उस समय पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को नहीं दी गई, उस समय भी उनको दे सकते, तब न देकर हमने यह स्टेट फार्म्स कारपोरेशन आफ इंडिया को दी, अब फिर उनको वापिस दे रहे हैं? दूसरा, यह आपने अभी तक नहीं बताया कि यह वाइफरकेशन क्यों कर रहे हैं? 2700 एकड़ पूरी लैंड क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहे? 1300 कर रहे हैं, बाकी 1400 का क्या होगा?

श्री बलराम जाखड़ : देखिए, उनको जब आवश्यकता हुई और जरूरत बढ़ी, पहले था, अब वहां बढ़ने के लिए गुंजाइश नहीं है चारों तरफ लुधियाना शहर बढ़ गया है, अगर आप वहां जाकर देखें तो आपको पता लगेगा जब उस आवश्यकता को पूरा करना है, उस यूनिवर्सिटी को पूरा चलाना है और उसका पूरा फायदा उठाना है तो आवश्यक है कि उसको और ज्यादा जमीन दी जाए। उनको जितनी आवश्यकता है, दी जाएगी और यह मिल-मिलाकर हम दोनों काम करेंगे, उसमें कोई नुकसान होने की गुंजाइश तो नहीं है, उसमें ज्यादा उत्पत्ति होगी, अच्छा फायदा होगा। ठीक ढंग से काम चालू किया जाएगा और कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो किसान काम करेगा और जो वहां लेबर काम करने वाला है, उसको पैसा ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला है।

SHRI SUKOMAL SEN: My question is about the condition of the workers there. These employees were transferred to it when the State Farm was leased to the Government of Punjab by the S.F.C.I. on 1-6-1971. These employees became employees of the S.F.C.I. Now, again the same employees are being taken over by the Punjab Agricultural University. I do not know whether the entire staff of the earlier organisation are being taken over by the Punjab University. I would like to know from the hon. Minister about the changes that took place in their service conditions. One was when it was taken over in 1971. What were their service conditions at that time? Now, how many workers will come under the Punjab Agricultural University? When they come under the Punjab Agricultural University, they are likely to become employees of the Punjab Agricultural University. In that case how is the Government going to protect the interests of the staff and workers of the farm? What will be their *inter-se* seniority? What is

the total number of workers involved in the farm?

SHRI BALRAM JAKHAR : The question simply remains that nothing is as consistent as change. It is changing. According to the changing times, we took over that farm and it was leased. The 20-year lease is over.

SHRI SUKOMAL SEN: How are you going to protect the interests of the workers? That is my question.

SHRI BALRAM JAKHAR: We are not only to protect the interests of the workers and labourers, but we are also to protect the interests of the farmers and the people of India. That is what we are going to do. That we have already done. I may assure you that nothing untoward is going to happen to anybody.

MR. CHAIRMAN: The Short Notice Question is also over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Privatisation of DMS

*344. SHRI MOHINDER SINGH LATHER:

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Delhi Milk Scheme (DMS) has been running into heavy loss year after year;

(b) if so, what is the estimated loss since March, 1991 till March, 1993, (current financial year) stating the factors responsible for such losses;

(c) whether Government propose to set up a committee to go into the working of the Delhi Milk Scheme in its entirety or to hold a CBI enquiry;

(d) if so, the steps taken by Government in this direction and to remove the deficiencies|corruption in the DMS;

(e) if answer to (c) is in negative, the reasons therefor;

(f) whether government propose to privatise the DMS;

(g) whether any offer has been received by Government in the matter; and

(h) if so, the details thereof stating the procedure to be adopted in privatising the DMS?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) Yes, *Sir.*

(b) The estimated losses of DMS since March, 1991 to March, 1993 are as under:—

Year	Loss (Rs. in crores)
1991-92	35.12
1992-93	33.18

(c) No, Sir.

(d) Various steps have been taken by DMS to improve its functioning. The staff strength of DMS has been reduced by about 21 per cent whereas its installed capacity has been increased from 3.75 lakh litres per day to 5.00 lakh litres per day. In addition DMS have taken various steps to reduce its losses by effecting economies in the consumption of various utilities|consumables like polythene film, petrol, rationalisation of disribution routes and revision of sale price of milk from time to time.

(e) The losses are mainly due to the fixation of sale price of Delhi Milk Scheme milk lower than the cost of production. The selling price of milk is fixed on lower side than the cost of production in order to fulfil its avowed policy to provide a remunerative market to the producers of milk on the one hand and to make available quality milk at reasonable rates to the citizens of Delhi|New Delhi on the other.